# ४ आर्थिक विकास

भारत की आर्थिक नीति का इस पाठ में हम अध्ययन करेंगे। इसमें विशेष रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था का स्वीकार, पंचवर्षीय योजनाएँ और उनकी सफलता-विफलता, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, बीस सूत्री कार्यक्रम, मिल मजदूरों की हड़ताल और वर्ष १९९१ की नई आर्थिक नीति का अध्ययन करेंगे।

**मिश्रित अर्थव्यवस्था :** भारत स्वतंत्र होने के पहले से ही हमें किस अर्थव्यवस्था को स्वीकार करना है, इस विषय में विचार मंथन चल रहा था। प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने किसी भी अर्थव्यवस्था को लेकर अतिवादिता की भूमिका को स्वीकारने के स्थान पर बीच के मार्ग का अवलंब किया। कुछ देशों में पूँजीवादी अर्थव्यवस्था प्रचलित थी तो कुछ देशों में समाजवादी अर्थव्यवस्था व्यवहार में थी। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के कुछ लाभ होते हैं और कुछ हानियाँ भी होती हैं।

पूँजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन निजी स्वामित्व के नियंत्रण में होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन समाज अर्थात सरकार के स्वामित्व के अधीन होते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था निजी और सार्वजनिक ऐसे दोनों क्षेत्रों में कार्यरत रहती है। दोनों अर्थव्यवस्थाओं की अपेक्षा भारत ने 'मिश्रित अर्थव्यवस्था' को प्राथमिकता दी। इस अर्थव्यवस्था में हमें तीन भेद दिखाई देते हैं।

**(१) सार्वजनिक क्षेत्र :** इस क्षेत्र के उद्योग-धंधे पूर्णतः सरकार के नियंत्रण और प्रबंधन के अंतर्गत होते हैं। जैसे- रक्षा सामग्री उत्पादन।

**(२) निजी क्षेत्र :** इस क्षेत्र के उद्योग-धंधे पूर्णतः निजी उद्योजकों के स्वामित्व के अधीन होते हैं। फिर भी उन उदयोग-धंधों पर सरकार का निरीक्षण एवं नियंत्रण होता है। जैसे उपभोक्ता वस्तुएँ।

**(३) संयुक्त क्षेत्र :** इस क्षेत्र में कुछ उद्योग निजी उद्योजकों के स्वामित्व के तथा कुछ सरकारी प्रबंधन के अधीन चलाए जाते हैं।

मिश्रित अर्थव्यवस्था सुचारु रूप से चलने के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बीच समन्वय होना आवश्यक होता है। इस अर्थव्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य यह है कि अधिकाधिक उत्पादन और उसमें बड़ी मात्रा में लोगों का सहभागी होना। इस अर्थव्यवस्था में पूँजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था के उत्तम तत्त्वों का समन्वय साधने का प्रयास किया गया है। लाभ प्राप्ति की प्रेरणा, उपक्रमशीलता, अनुशासन, कालबद्ध नियोजन आदि बातों को मिश्रित अर्थव्यवस्था में उपेक्षित नहीं किया जा सकता।

इस अर्थव्यवस्था में देशहित को प्रधानता देने की प्रवृत्ति होती है। दीर्घकालीन विकास पर अधिक बल दिया जाता है। रक्षा, वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, सड़कें, रेल, नहरें, बंदरगाह और विमान पत्तन निर्माण जैसे क्षेत्रों के लिए विपुल पूँजी निवेश की आवश्यकता होती है; परंतु ये क्षेत्र बहुत देरी से लाभ देते हैं। परिणामतः इस क्षेत्र में निजी उद्योजक बड़ी मात्रा में आगे नहीं आते हैं। ऐसे समय सरकार को ही अगुवाई करनी पड़ती है।

ऊपर बताई गई पद्धति के आधार पर भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढाँचे का उपयोग कर तथा पंचवर्षीय योजनाओं को अंगीकार कर अपनी विकास यात्रा प्रारंभ की। वर्ष १९७३ में बनी आर्थिक नीति के कारण विकास की गति में तेजी आई। इस नीति के अनुसार भारी उद्योग, उद्योजक घराने और विदेशी उद्योगों के प्रभाव को नियंत्रण में लाना और प्रादेशिक विकास का संतुलन साधना जैसे मुद्दों को प्राथमिकता दी गई। लघु उद्योग, ग्रामोद्योग, घरेलू उद्योग के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। सहकारिता क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान देना प्रारंभ हुआ।

## पंचवर्षीय योजना

भारत के स्वतंत्र होने तक विदेशी सत्ता ने भारत का पूरा-पूरा आर्थिक शोषण किया था। देश के सम्मुख दरिद्रता, बेरोजगारी, जनसंख्या में

होती वृद्धि, निम्न स्तर का जीवन स्तर, कृषि और उद्योग-धंधे अल्प उत्पादन क्षमता तथा ज्ञान विज्ञान और तकनीकी ज्ञान से संबंधित पिछड़ापन जैसी विकट और गंभीर समस्याएँ थीं। उनको हल करने के लिए योजनाओं की आवश्यकता थी।

वर्ष १९५० में भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया। प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू इस योजना आयोग के अध्यक्ष थे।

इस योजना आयोग ने पाँच वर्षों की योजना तैयार की जिसमें कृषि और ग्राम का विकास होगा, संतुलित औद्योगिकीकरण और न्यूनतम जीवन स्तर का प्रावधान होगा। जिसमें योजनाओं की रूपरेखा बनाने और कार्यान्वयन में लोगों का प्रतिभाग होगा और प्रत्येक व्यक्ति का विकास होगा। इस योजना को ही 'पंचवर्षीय योजना' कहते हैं।

**योजना आयोग का मौलिक सिद्धांत :** किसी देश के समग्र संसाधनों का अनुपातबद्ध वितरण और वहाँ के मनुष्य श्रम का उचित उपयोग उस देश की जनता की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए किया जाना चाहिए। यह योजना आयोग का मौलिक सिद्धांत है।

## योजना आयोग के उद्देश्य

भारत के योजना आयोग के सामान्य उद्देश्य इस प्रकार हैं।

(१) राष्ट्रीय आय में वृद्धि।

(२) मूलभूत उद्योग-धंधों को वरीयता देकर शीघ्रगति से औद्योगिकीकरण करवाना।

(३) कृषि उत्पादनों में वृद्धि लाना; जिससे देश खाद्यान्न के विषय में आत्मनिर्भर बन सके।

(४) बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना और देश के मनुष्य श्रम का पूर्णतः उपयोग कर लेना।

(५) आय और संपत्ति के बीच उत्पन्न विषमता को दूर करना।

(६) वस्तुओं के मूल्य स्थिर स्तर पर रखना।

(७) परिवार नियोजन के माध्यम से बढ़ती जनसंख्या की रोक-थाम करना।

(८) दरिद्रता को दूर कर जीवन स्तर को ऊँचा उठाना।

(९) सामाजिक सेवाओं का विकास करना।

(१०) आर्थिक क्षेत्रों को आत्मनिर्भर बनाना।

**प्रथम पंचवर्षीय योजना (१९५१- १९५६)**

इस योजना के अंतर्गत कृषि, सामाजिक विकास, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा संसाधन, ग्रामीण एवं लघु उद्योग, बड़े उद्योग और खनिज संसाधन, परिवहन एवं दूरसंचार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पर व्यय किया गया। योजनाबद्ध आर्थिक विकास की नींव रखने वाली यह पंचवर्षीय योजना थी।

**दूसरी पंचवर्षीय योजना (१९५६-१९६१)** इस योजना द्वारा औद्योगिकीकरण का महत्त्वाकांक्षी उद्देश्य पूर्ण करना था। फलतः दुर्गापुर, भिलाई, रुरकेला में इस्पात के कारखाने, सिंदरी में रासायनिक खाद कारखाना, चित्तरंजन में रेल इंजन का कारखाना, पेरांबूर में रेलगाड़ी के डिब्बे निर्माण का कारखाना, विशाखापट्टनम में जहाज निर्माण का कारखाना जैसे विशाल और भारी उद्योग-धंधे और कारखाने सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित किए गए। कृषि को जलापूर्ति

भिलाई – इस्पात का कारखाना

करने के लिए भाखड़ा-नंगल, दामोदर जैसे विशाल बाँध बनाए गए। इस योजना के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई।

**तीसरी पंचवर्षीय योजना (१९६१-१९६६):** इस योजना में उद्योग और कृषि के विकास के बीच संतुलन और समन्वय साधना था। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना, भारी उद्योग, परिवहन और खनिज उद्योगों का विकास करना, विषमता का उन्मूलन करना और रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध कराना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे।

तीसरी पंचवर्षीय योजना के पश्चात तीन एक वर्षीय योजनाएँ (१९६६-१९६९) चलाई गईं। इस कालावधि में भीषण अकाल का सामना करना पड़ा। चीन का आक्रमण और पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के कारण सरकार को विकास कार्यों की अपेक्षा रक्षा और अकाल निवारण की ओर अधिक ध्यान देना पड़ा। इन सभी बातों से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा दबाव आ गया।

**चौथी पंचवर्षीय योजना (१९६९-१९७४):** इस योजना के उद्देश्य निर्धारित करते समय यह निश्चित किया गया कि भारत को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, सरकार को मूलभूत उद्योगों का विकास करना चाहिए, आर्थिक विकास की गति बढ़ानी चाहिए और समाजवादी सामाजिक ढाँचे की ओर ध्यान देना चाहिए। इस पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश के प्रमुख १४ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह पंचवर्षीय योजना अपेक्षानुसार सफल नहीं रही। चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में बांगला देश युद्ध के परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्था को सहने पड़े। साथ ही शरणार्थियों का व्यय सहन करना पड़ा। सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, रेल कर्मचारियों की वेतन वृद्धि, अंतरराष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल की बढ़ती दरें जैसी बातों से भारत की अर्थव्यवस्था को कई आघात सहने पड़े।

**पाँचवीं पंचवर्षीय योजना (१९७४-१९७९):** निर्धनता को दूर कर देश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का प्रमुख उद्देश्य सम्मुख रखकर यह योजना तैयार की गई। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय आय में वृद्धि लाना, बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराना, शिक्षा, पौष्टिक भोजन, पेयजल की पूर्ति करना, ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा की सुविधाएँ पहुँचाना, ग्रामीण भागों में विद्युत आपूर्ति और दूरसंचार के साधन पहुँचने के लिए सड़कों का निर्माण कराना, समाज कल्याण की योजनाओं को व्यापक स्तर पर कार्यान्वित करना, कृषि का विकास करवाना, मूलभूत उद्योग-धंधों में वृद्धि लाना, खाद्यान्न और अन्य जीवनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी एकाधिकार प्रणाली द्वारा करके उनकी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थाओं द्वारा निर्धनों को उचित दामों में पूर्ति करना जैसे उद्देश्यों का समावेश था।

पाँचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में दरिद्रता का निवारण करना और रोजगार को बढ़ाना संभव नहीं हुआ।

वर्ष १९७७ में लोकसभा चुनाव में काँग्रेस पार्टी की पराजय हुई। जनता पार्टी सत्ता में आई। नई सरकार ने मार्च १९७८ के अंत में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर अप्रैल १९७८ से श्रृंखलाबद्ध योजना प्रारंभ की; परंतु वह विफल रही। वर्ष १९८० में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव संपन्न हुए और काँग्रेस पार्टी सत्ता में आई। इस सरकार ने श्रृंखलाबद्ध योजना को बंद कर पुनः पूर्ववत प्रणाली अर्थात पंचवर्षीय योजना को प्रारंभ किया।

**छठी पंचवर्षीय योजना (१९८०-१९८५):** इस योजना में दरिद्रता उन्मूलन और रोजगार निर्माण को वरीयता दी गई थी। इस योजना के उद्देश्य इस प्रकार थे।

अर्थव्यवस्था की विकास दर में उल्लेखनीय वृद्धि करना, दरिद्रता और बेरोजगारी को कम करना। ऐसी नीति को स्वीकारना कि लोग छोटा परिवार पद्धति को स्वेच्छा से स्वीकारेंगे, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखा जा सकेगा।

छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत निम्न कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया।

- एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)
- ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (RLEGP)
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP)
- सलेम इस्पात परियोजना

**सातवीं पंचवर्षीय योजना (१९८५-१९९०) :** इस योजना में खाद्यान्न, रोजगार और उत्पादकता पर बल दिया गया था। विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक न्याय का सक्षमता से कार्यान्वयन करना, उत्पादन तकनीकी विज्ञान में सुधार करना, राष्ट्रीय आय में प्रतिवर्ष ५% वृद्धि लाना, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य थे।

इस योजना के अंतर्गत निम्न कार्यक्रम प्रारंभ किए गए।

* जवाहर रोजगार योजना। * इंदिरा आवास योजना। * दस लाख कुएँ योजना।

रोजगार निर्माण करने की दृष्टि से सातवीं पंचवर्षीय योजना महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई।

**आठवीं पंचवर्षीय योजना (१९९२-१९९७) :** इस योजना के अंतर्गत निजी क्षेत्र को अधिकाधिक अवसर दिए गए।

इस योजना की विशेषताएँ इस प्रकार थीं।

राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर ६.५% तक बनाए रखना, जनसंख्या वृद्धि की रोक-थाम करना, परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना, प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिक विस्तार कर निरक्षरता का उन्मूलन करना।

इस योजना के अंतर्गत निम्न कार्यक्रम प्रारंभ किए गए।

* प्रधानमंत्री रोजगार योजना * महिला समृद्धि योजना * राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक सहयोग योजना * मध्याह्न भोजन योजना * इंदिरा महिला योजना * गंगा कल्याण योजना

आठवीं पंचवर्षीय योजना में निजी क्षेत्र का महत्त्व बढ़ गया। इस योजना में वर्ष १९९१ में सरकार द्वारा स्वीकारी गई उदार और मुक्त आर्थिक नीति का प्रतिबिंब दिखाई देता है।

**नौवीं पंचवर्षीय योजना(१९९७-२००२) :** इस योजना में कृषि और ग्रामीण विकास को प्रधानता दी गई थी। आर्थिक विकास की दर में वृद्धि लाना, मूलभूत क्षेत्र में स्वस्थ प्रतियोगिता निर्माण करना, विदेशी निवेश के लिए औद्योगिक नीति को नई दिशा प्रदान करना इस योजना के उद्देश्य थे।

इस योजना के अंतर्गत स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, भाग्यश्री बालकल्याण योजना, राजराजेश्वरी महिला कल्याण योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, अंत्योदय अनाज योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना आदि कार्यक्रम चलाए गए।

इस योजना में संचार व्यवस्था और सेवा क्षेत्र की अपेक्षित मात्रा में उन्नति हुई। निर्माण कार्य और दूरसंचार क्षेत्रों में वृद्धि हुई।

## बैंकों का राष्ट्रीयकरण:

पंडित नेहरू और लालबहादुर शास्त्री के कार्यकाल में भारत में बैंकिंग व्यवसाय पर निजी क्षेत्र का एकाधिकार था। ये बैंक उद्योग समूह का प्रतिनिधित्व करते थे। इन बैंकों के निदेशक अपने उद्योगों का विकास और लाभ को बढ़ाने में कार्यरत रहते थे। इसकी रोक-थाम करने के लिए सरकार ने वर्ष १९५५ में 'इम्पीरियल बैंक' का राष्ट्रीयकरण किया और उसे 'भारतीय स्टेट बैंक' में परिवर्तित किया। इस बैंक ने अल्पावधि में ही संपूर्ण देश में अपनी शाखाएँ खोलकर सरकारी विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाना प्रारंभ किया।

**राष्ट्रीयकरण की पृष्ठभूमि:** भारत ने स्वातंत्र्योत्तर कालावधि में मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया था। योजनाओं को कार्यान्वित करते समय यदि घाटा हो जाता है तो उसे पूरा करने के लिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना आवश्यक था। राष्ट्रीयकरण होने के बाद इन बैंकों को होने वाला लाभ सरकारी कोष में जमा होने वाला था। इसी के साथ लघु और मंझोले उद्योग से संबंधित विकास नीति को कार्यान्वित करना भी आवश्यक था। लालबहादुर शास्त्री ने खाद्यान्न की कमी को दूर करने और अकाल पर मात करने के लिए हरित क्रांति का प्रयोग प्रारंभ किया था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल

**क्या आप जानते हैं?**

प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने १९ जुलाई १९६९ को १४ बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इनमें इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बरोड़ा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नैशनल बैंक, सिंडीकेट बैंक, यूनायटेड बैंक ऑफ इंडिया, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक, (यूको बैंक), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इन १४ बैंकों का समावेश था। वर्ष १९८० में और छह बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

में काँग्रेस पार्टी में समाजवादी विचारों से प्रेरित होकर 'काँग्रेस फोरम फॉर सोशालिस्ट एक्शन' दल ने व्यापारी बैंकों के राष्ट्रीयकरण की माँग की। इस निर्णय को कम्युनिस्ट पार्टी का भी समर्थन प्राप्त था।

**बीस सूत्री कार्यक्रम :** १ जुलाई १९७५ को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की और विकसित राष्ट्र की दिशा में गतिमान प्रगति करने के प्रयासों का संकल्प किया। इस कार्यक्रम में प्रमुख प्रावधान इस प्रकार थे।

(१) कृषि और शहरी क्षेत्रों में अधिकतम भूमि धारण कानून (चकबंदी कानून), संपत्ति का समान वितरण, खेत मजदूरों को न्यूनतम वेतन, जल संवर्धन योजनाओं में वृद्धि करना।

(२) श्रमिकों का उद्योग क्षेत्र में प्रतिभाग, राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना और बेगार से मुक्ति।

(३) कर चोरी की प्रवृत्ति, आर्थिक अपराध और तस्करी की रोक-थाम।

(४) जीवनावश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण, राशनिंग व्यवस्था में सुधार करना।

(५) हथकरघा क्षेत्र के विकास द्वारा उत्तम वस्त्रोद्योग का निर्माण, दुर्बल वर्गों की ऋण से मुक्ति, आवास निर्माण, दूरसंचार सुविधाएँ, विद्यालयों के लिए शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराना।

**श्रमिक समस्या :** मुंबई में पहली कपड़ा मिल ११ जुलै १८५१ को कावसजी डावर ने

कपड़ा मिल

शुरू की। कालांतर में दादर, परेल, भायखला, शिवडी, प्रभादेवी और वरली में कपड़ा मिलें खुल गईं। यह क्षेत्र गिरणगाँव के रूप में पहचाना जाने लगा।

८० के दशक में श्रमिकों में असंतोष निर्माण हुआ। इसके लिए अन्य क्षेत्रों में उत्पन्न हुई स्थिति कारण बनी। कुछ उद्योगों में श्रमिकों के वेतन में वृद्धि हो रही थी। उन्हें बोनस की अधिक राशि मिल रही थी। कपड़ा मिल श्रमिकों की तुलना में उन्हें अधिक सुविधाएँ प्राप्त हो रही थीं।

**क्या आप जानते हैं?**

महात्मा जोतीराव फुले के सहयोगी नारायण मेघाजी लोखंडे इनके प्रयासों के परिणामस्वरूप यह निर्णय हुआ कि १ जनवरी १८८२ से मिल श्रमिकों को सप्ताह में एक दिन 'रविवार' को छुट्टी दी जाए।

वर्ष १९८१ की दीवाली में श्रमिकों को अपेक्षा थी कि उन्हें २०% बोनस मिलेगा। श्रमिकों का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ कर रहा था। इस संघ ने श्रमिक वर्ग को विश्वास में न लेकर मालिकों के साथ बातचीत की और ८ से १७% पर बोनस को लेकर समझौता किया। बोनस में की गई यह कटौती असंतोष की चिंगारी सिद्ध हुई। कुछ श्रमिक डॉ. दत्ता सामंत से मिले। उन्होंने डॉक्टर सामंत से नेतृत्व स्वीकारने का निवेदन किया। ६५ मिलों के श्रमिक इकट्ठे आए और दत्ता सामंत

**क्या आप जानते हैं?**

सांस्कृतिक दृष्टि से भी श्रमिक वर्ग ने लोकनाट्य, लोककला और साहित्य जैसे क्षेत्रों में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अण्णाभाऊ साठे, शाहीर अमर शेख, शाहीर साबळे आदि अनेक लोकशाहीर (लोककवि) अपने जनजागरण कार्यक्रमों के कारण लोकप्रिय हुए थे। नारायण सुर्वे, नामदेव ढसाळ आदि कवियों ने मजदूरों की भीषण वास्तविकता के दर्शन अपनी कविताओं द्वारा कराए।

हड़ताल का नेतृत्व करने लगे। १८ जनवरी १९८२ को मुंबई में ढाई लाख मजदूर हड़ताल पर चले गए। गिरणगाँव की मशीनों की ठकठक रुक गई, मानो मुंबई का हृदय ही बंद हो गया था।

मुख्यमंत्री बै. अ. र. अंतुले ने इस समस्या का हल निकालने के लिए त्रिदलीय समिति का गठन किया। आगे चलकर बाबासाहेब भोसले मुख्यमंत्री बने। उनकी भूमिका थी कि कानूनी तौर पर सरकार केवल राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के साथ ही बातचीत करेगी। डॉ. दत्ता सामंत ने यह कानून रद्द करने की माँग की।

हड़ताल के प्रारंभिक समय में मजदूरों को उनके गाँवों से सहायता मिलने लगी। प्रारंभ में एक-दूसरे को सहयोग देना मजदूरों को कठिन प्रतीत नहीं हुआ। विभागों के अनुसार समितियाँ बनाकर उन्होंने अनाज और सहायता राशि का वितरण किया। वाम दलों ने हड़ताल को समर्थन दिया था लेकिन जैसे-जैसे हड़ताल खींची जाने लगी वैसे ही मजदूरों में फूट पैदा करने के प्रयास प्रारंभ हुए। हड़ताल को छह महीने पूर्ण हुए। केंद्र सरकार ने हड़ताल को पूरी तरह उपेक्षित किया। मजदूरों ने 'जेल भरो आंदोलन'शुरू किया। सितंबर १९८२ में डेढ़ लाख मजदूरों का जुलूस महाराष्ट्र विधान सभा पर गया परंतु विफलता हाथ लगी। हड़ताल को एक वर्ष पूर्ण हुआ। यह पहली हड़ताल थी जो इतने प्रदीर्घ समय तक चली। हड़ताल की कालावधि में लगभग डेढ़ लाख मजदूर बेरोजगार बने।

कपड़े की तुलना में पॉलिएस्टर को महत्त्व प्राप्त हुआ था। परिणामतः पहले से ही मिल की कपड़ा बिक्री पर प्रतिकूल परिणाम हुआ था। कपड़ा मिलें मुंबई से सूरत और गुजरात में स्थलांतरित हो गई थीं। केंद्र सरकार ने १३ मिलों का राष्ट्रीयकरण किया। इस समस्या को हल करने के लिए मध्यस्थ न्यायाधिकरण का गठन किया गया; परंतु इसमें सफलता नहीं मिली।

**नई आर्थिक नीतिः** आधुनिक भारत के इतिहास में वर्ष १९९१ महत्त्वपूर्ण वर्ष रहा। दसवें लोकसभा चुनावों के पश्चात केंद्र में पी.वी. नरसिंह राव प्रधानमंत्री बने।

पी. वी. नरसिंह राव

उन्होंने तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के सहयोग से भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए नई आर्थिक नीति को स्वीकार किया। इसके लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में मौलिक परिवर्तन किए। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक प्रवाह में ले आए।

उस समय भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी विकट बनी हुई थी। पी.वी. नरसिंह राव से पूर्व चंद्रशेखर की सरकार थी। इस सरकार के कार्यकाल में मुद्रास्फीति की दर १७ प्रतिशत थी। आर्थिक वृद्धि दर १.१ प्रतिशत से घट गई थी। भारत के पास विदेशी मुद्रा का भंडार इतना कम रह गया था कि आयात एक सप्ताह तक ही किया जा सकता था। विदेशी ऋण का भुगतान करना और उसका ब्याज देना भी असंभव हो गया था। मई १९९१ में चंद्रशेखर सरकार के शासन काल में सरकार ने कुछ सोना बेचकर और कुछ गिरवी रखकर स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। चंद्रशेखर से पूर्व विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने सभी किसानों का सरसरी तौर पर ऋण माफ कर १० हजार करोड़ रुपयों से अधिक का भार अर्थव्यवस्था पर लाद दिया था। केंद्र और राज्य सरकारों के एकत्रित

अंतर्गत ऋण का सकल राष्ट्रीय आय से अनुपात लगभग ५५% हो गया। वर्ष १९८०-८१ में विदेशी ऋण २३५० करोड़ डॉलर्स तक बढ़ गया था। अब यह ऋण वर्ष १९९०-९१ में ८३८० करोड़ डॉलर्स तक बढ़ गया। इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार केवल १०० करोड़ डॉलर्स था। इस स्थिति के लिए इराक द्वारा कुवैत पर आक्रमण किए जाने से तेल के बढ़ते दाम भी कारण था। भारत के लिए विदेशी ऋण खड़ा करना कठिन हो गया। अनिवासी भारतीयों ने भी विदेशी मुद्रा में किया हुआ अपना निवेश निकाल लेना प्रारंभ किया।

**उपाय योजना :** इस स्थिति से उबरने के लिए पी.वी.नरसिंह राव ने डॉ. मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त किया। डॉ. मनमोहन सिंह ने त्रुटि सुधार उपाय योजना (करेक्टिव मेजर्स) बनाई। स्थितियों में परिवर्तन होना प्रारंभ हुआ।

डॉ. मनमोहन सिंह

उन्होंने विदेशी निवेश पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। उद्योग क्षेत्र में प्रचलित अनुज्ञप्ति प्रणाली (लाइसेंस सिस्टम) १८ उद्योगों तक सीमित रखी। सार्वजनिक उद्योग क्षेत्रों में लाभ घटता जा रहा था और श्रमिकों की कार्यक्षमता प्रभावित हो रही थी। इसे ध्यान में रखकर उन्होंने सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र निजी उद्योग क्षेत्रों के लिए खोल दिए। शेअर बाजार पर नियंत्रण लाने के लिए वर्ष १९९२ में सेबी (सेक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) का गठन किया। नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का संगणकीकरण किया गया। मंदी के संकट को दूर करने को वरीयता दी गई।

डॉ. मनमोहन सिंह के अपने प्रथम वित्त मंत्री पद के कार्यकाल में भारत के विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। बैंक ऑफ इंग्लैड में गिरवी रखा अपना स्वर्ण भारत अपने देश में वापस ले आया। सरकार को देश के पूँजीपति वर्ग और मध्यवर्ग का समर्थन प्राप्त हुआ। सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र मुक्त कर दिया। परिणामस्वरूप संपूर्ण देश में मोबाइल फोन की सेवाएँ प्रारंभ हुईं। डॉ. मनमोहन सिंह ने विश्व व्यापार संगठन के अनुबंध (करार) पर हस्ताक्षर कर निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण को प्रारंभ किया।

**वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (विश्व व्यापार संगठन) :** भारत ने वर्ष १९९५ में 'वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन' **(WTO)** का सदस्यत्व स्वीकार किया। इस संगठन का उद्देश्य निम्नानुसार था।

अलग-अलग देशों के बीच चलने वाले व्यापार को मुक्त, बंधनरहित बनाना। अंतरराष्ट्रीय मुक्त व्यापार में बाधा बनने वाले और भेदभाव उत्पन्न करने वाले कानूनों नियमों, बंधनों और नीतियों को समाप्त करना। वैश्विक व्यापार का विधिवत बहुपक्षीय व्यवस्था द्वारा नियमन करना।

**WTO** के अस्तित्व में आने से पूर्व 'गैट' अस्तित्व में था अर्थात 'जनरल एग्रीमेंट ऑन टेरिफ्स एंड ट्रेड' नाम का यह संगठन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहा था। यह संगठन व्यापार का नियमन करता था। भारत में **WTO** को लेकर अति परस्पर विरोधी विचारधाराएँ थीं। इतना होने पर भी **WTO** के सदस्यत्व को स्वीकारने का निर्णय किया गया। 'विश्व व्यापार संगठन' के नियम-प्रावधान, अनुदान, आयात-निर्यात, विदेशी निवेश हेतु संरक्षित क्षेत्र, कृषि, तकनीकी विज्ञान और सेवाओं से संबंधित हैं। भारत के सदस्य बनने के बाद से बिजली, जल, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों का बड़ी शीघ्रता से व्यापारीकरण हुआ। 'विश्व व्यापार संगठन' के विभिन्न प्रतिवेदनों (रिपोर्टों) के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे वाली जनसंख्या में कमी लाना, बालमृत्यु दर को कम करना, पेयजल, धोवनजल से संबंधित सुविधाओं की उपलब्धता जैसे क्षेत्रों में भारत ने सुधार किए हैं।

विश्व व्यापार संगठन के समान भारत ने

कालांतर में 'दक्षिण एशियाई व्यापार प्रधानता अनुबंध' (साऊथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेडिंग एरेंजमेंट - **SAPTA**) पर हस्ताक्षर किए। भारत ने सार्क देशों के लिए विभिन्न वस्तुओं के आयात पर लगे प्रतिबंध हटा दिए। आयात शुल्क में छूट दी। भारत के बीमा क्षेत्र निजी और विदेशी निवेश के लिए खोल दिए।

इस तरह हमने स्वतंत्रोत्तर भारत की आर्थिक प्रगति का अध्ययन किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था से लेकर वैश्वीकरण तक की हमने यात्रा की। अगले पाठ में हम भारत द्वारा अन्य क्षेत्रों में की गई प्रगति का अध्ययन करेंगे।

## स्वाध्याय

**१. (अ) दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पूर्ण कीजिए।**

(१) १९ जुलाई १९६९ को देश के प्रमुख ..... बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
(अ) १२ (ब) १४ (क) १६ (ड) १८

(२) बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा..... ने की।
(अ) पं. नेहरू
(ब) लालबहादुर शास्त्री
(क) इंदिरा गांधी
(ड) पी.वी. नरसिंह राव

**(ब) निम्न में से असंगत जोड़ी पहचानिए और लिखिए।**

(१) कावसजी डावर - इस्पात का कारखाना
(२) डॉ.दत्ता सामंत - मिल मजदूरों का नेतृत्व
(३) ना.मे. लोखंडे - मिल मजदूरों को छुट्टी
(४) नारायण सुर्वे - कविताओं द्वारा श्रमिकों का जीवन दर्शन

**२.(अ) दी गई सूचना के अनुसार कृति कीजिए।**

निम्न तालिका पूर्ण कीजिए।

| पंचवर्षीय योजना | कालावधि | उद्देश्य |
|---|---|---|
| प्रथम | ---- | कृषि, सामाजिक विकास |
| दूसरी | वर्ष १९५६-१९६१ | औद्योगिकीकरण |
| तीसरी | ---- | विषमता का उन्मूलन,रोजगार अवसर के विस्तार, राष्ट्रीय आय में वृद्धि |
| ..... | १९६९-१९७४ | वैज्ञानिक अनुसंधान, स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन |
| पाँचवीं | ---- | ..... |

**(ब) टिप्पणी लिखिए।**

(१) मिश्रित अर्थव्यवस्था
(२) बीस सूत्री कार्यक्रम।

**३. निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट कीजिए।**

(१) स्वतंत्र भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया।
(२) वर्ष १९६९ में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।
(३) मिल मजदूरों ने हड़ताल की।

**४. निम्न प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए।**

(१) आठवीं पंचवर्षीय योजना में कौन-से कार्यक्रम प्रारंभ किए गए।

(२) दूसरी पंचवर्षीय योजना में किन परियोजनाओं का प्रारंभ किया गया?

**उपक्रम**

(१) अंतरजाल (इंटरनेट) की सहायता से **WTO** संगठन की जानकारी प्राप्त कीजिए। जैसे- बोध चिह्न सदस्य देश, उद्देश्य, कार्यक्रम आदि।

(२) राष्ट्रीयकृत बैंक/उसकी शाखा में जाइए और उनके कामकाज की जानकारी प्राप्त कीजिए।

7G1ZGD